handicapped persons. This programme was introduced in January 1980 following unprecedented drought and later floods. The programme is estimated to cover 66 lakh beneficiaries in the country.

चीनी उद्योग के लिए दीर्घावधि नीति

1981. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक क्षमता वाले चीनी, गुड़ तथा खांडसारी उद्योगों की मूल समस्याओं को हल करने के लिए एक दीर्घावधि नीति तथा प्रक्रिया बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो आम उपभोक्ता को इससे कितना लाभ प्राप्त होगा ; और

(ग) क्या सरकार चीनी का 'रक्षित भण्डार' बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) और (ख). सरकार इन उद्योगों के समन्वित विकास और सन्तोषजनक वृद्धि तथा इसके साथ साथ गन्ना उत्पादकों और मीठे के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रख कर हमेशा एक दीर्घकालीन नीति तयार करने का प्रयास करती रही है । तथापि, ऐसी नीति तैयार करने में कई दबावों के अध्यधीन रहना पड़ता है क्योंकि गन्ना जो कि चीनी, गुड़ तथा खण्डसारी के निर्माण के लिए सांझा और प्रमुख कच्चा माल है, के उत्पादन, उपलब्धता मूल्यों आदि और इन वस्तुओं के उत्पादन, उपलब्धता और मूल्यों में भी वर्ष प्रतिवर्ष भारी उतार चढ़ाव आता है जिससे इन बदलती हुए परिस्थितियों का सामना करने के लिए नीति पैरामीटरों में अल्पकालीन उपचारी उपाय और अस्थाई परिवर्तन करने लाजमी हो जाते हैं ।

सरकार ने चीनी नीति पैरामीटर के विभिन्न विकल्पों, अर्थात् पूर्ण नियंत्रण, विनियंत्रण और आंशिक नियंत्रण को अपनाया है और उसका यह विचार है कि दोहरी मूल्य नीति के साथ चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति में मूलत: बदलती परिस्थितियों की जरूरतें पूरी करने का अपेक्षित लचीलापन है ।

(ग) चालू मौसम के दौरान 52 से 54 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने की आशा है जो कि वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग पर्याप्त होगा । अत: चालू वर्ष बफर स्टाक तैयार करने के लिए उपयुक्त नहीं है तथापि, 1981–82 में गन्ना और चीनी के उत्पादन अपेक्षाकृत काफी अधिक होने की आशा है और इसलिए सरकार उस वर्ष में बफर स्टाक तैयार करने के बारे में विचार कर सकती है ।

बिहार की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को केन्द्र के नियंत्रण में लेना

1982. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश को 1979–80 तथा 1980–81 के दौरान बाढ़ तथा सूखे के कारण कुल कितनी हानि हुई और देश को हुई इस कुल हानि में से बिहार को कितने प्रतिशत हानि हुई; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार बिहार की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है ।

(ख) भारत सरकार का बिहार की बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।